RNI Regn.No.- 54447/78 स्थापित: 1978 Postal Reg. No. UA/NTL- 08/ 2024-26

पिघलता हिमालय

वर्ष 40 अंक 43 हल्द्वानी सम्वत् 2082 सोमवार 31 मार्च 2025 एक प्रति 5 रु., वार्षिक-200 रु. आजीवन 2000 रु.

संस्थापक- स्व.आनन्द बल्लभ उप्रेती
स्व.दुर्गा सिंह मर्तोलिया,
स्व.श्रीमती कमला उप्रेती

editorpighaltahimalay@gmail.com
Website-
www.pighaltahimalay.com

सम्पादक : श्रीमती गीता उप्रेती
संरक्षक : फली सिंह दत्ताल
मंगल सिंह मर्तोलिया

हकाहाक मची है उत्तराखण्ड में

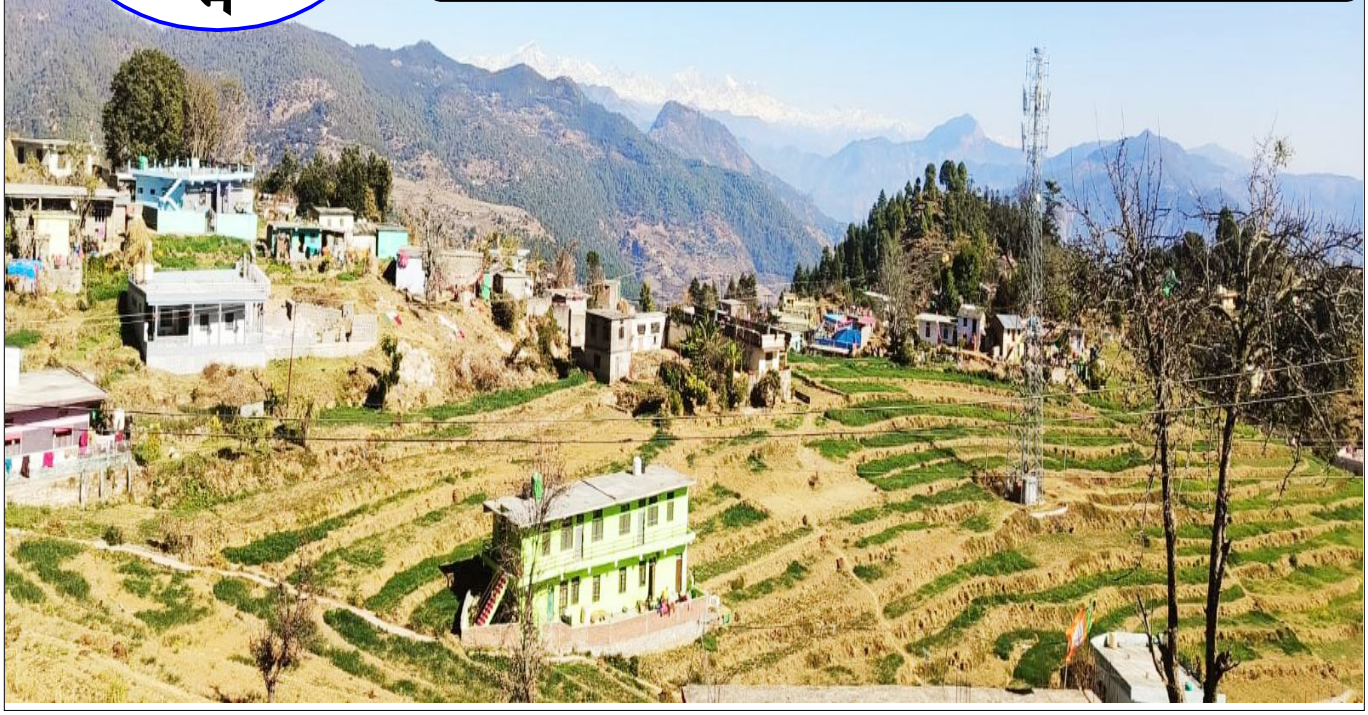

प्रेमचन्द तो जुवान चलाकर फंस गये लेकिन उनका क्या होगा जो छल रहे हैं

प्रदेश की राजनीति में उलटफेर का दौर अभी चलता रहेगा

कार्यालय प्रतिनिधि

उत्तराखण्ड की राजनीति में अभी उलटफेर का दौर चलता रहेगा। राज्य बनने के बाद से जिस प्रकार से इस प्रदेश में नेतागर्दी हाबी हुई है और किसी भी तरह से हर स्तर पर दबदबा बनाने की जुगत चल रही है वह आम जनता को झकझोर चुकी है। इस बीच सरकार के तीन साल होने का जश्न के अलावा नये फेरबदल का वातावरण नया सन्देश दे रहा है।

कहने को प्रेमचन्द अग्रवाल इकलौते पकड़ में आए। पकड़ में तो बहुत से नेता लेकिन हल्ला उनका ज्यादा है। प्रेमचन्द तो अपनी जुवान चलाकर फंस गये लेकिन उनका क्या होगा जो छल रहे हैं। विधायक-मंत्री की आड़ में किसने क्या कर डाला, जनता सब जान रही है लेकिन सब सुगम रास्ते चलने पर भलाई जान रहे हैं।

सदन के भीतर और सदन के बाहर कौन किस प्रकार के बोल बोलता रहा है सब चर्चा में हैं। रही-सही नेताओं के साथ वाले ही बता रहे हैं। फिलहाल युवा मुखर हैं और प्रेमचन्द अग्रवाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जगह-जगह प्रदर्शन कर उनकी विधायकी बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस, यूकेडी सहित तमाम संगठनों ने अनर्गल बयान बाजी के खिलाफ रोष जताते हुए प्रेमचन्द की विधायकी बर्खास्त की मांग के अलावा महेन्द्र भट्ट और ऋतु खण्डूरी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।

बताते चलें कि अपने बोलों से घिरे वित्त, शहरी विकास, आवास, जनगणना, संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल द्वारा 16 मार्च को इस्तीफे के बाद उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने संभाल लिये थे। सीएम की सहमति से राज्यपाल ने आदेश दिया था कि अग्रिम आदेशों तक अग्रवाल के सभी विभाग सीएम के पास ही रहेंगे। मंत्री के इस्तीफे के बाद प्रेमचन्द को तीन माह में यमुना कालोनी स्थित आवास करना होगा। कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे से नाराज उनके समर्थक व्यापारियों ने डोईवाला में अपने प्रतिष्ठान बन्द किये, जिन्हें प्रेमचन्द ने जाकर समझाया।

जनता में आखिर इतना गुस्सा क्यों उपजा है, इसके पीछे के कारणों में जाएं तो बताया जाता है कि प्रेमचन्द की दबंगता बढ़ती जा रही थी। इस आढ़ में उन्होंने कई कार्य शुरू कर डाले। आरोप सीधे से लगाया जा चुका है जो इनके पक्ष में बोल रहे थे वह भी किन्हीं कारणों से ही बोले।

उत्तराखण्ड लोक वाहिनी की अल्मोड़ा में हुई बैठक में उलोवा ने सरकार से विस में बजट सत्र के दौरान पहाड़ी समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने वलो निवर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द के सभी कार्यों की जांच कराने की मांग की है। बैठक में वक्ताओं ने प्रेमचन्द के त्यागपत्र देने को देर से उठाया गया कदम बताते हुए अमर्यादित आचरण करने वाले भाजपा नेता महेन्द्र

शेष पृष्ठ 2 पर

पूर्व मंत्री प्रेमचन्द के पुत्र पीयूष पर मुकदमा दर्ज

देहरादून। पूर्व मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल के पुत्र पीयूष अग्रवाल पर अधिकारियों की अनुमति के बिना सरकारी भूमि पर सड़क बनाने के आरोप में सार्वजनिक सम्पत्ति अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ है।

जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने बताया कि यह मुकदमा यमकेश्वर के एसडीएम अनिल चन्याल की अदालत में दर्ज किया गया है। पीयूष ने यह सड़क अपने प्रस्तावित होटल तक पहुंचाने के लिए बनाई एक जाँच रिपोर्ट में सरकारी जमीन पर मुख्य मार्ग से नीचे की ओर बिना किसी अनुमति के अवै रूप से 24 मीटर लम्बी, चार मीटर चौड़ी और डेढ़ मीटर गहरी सड़क का निर्माण करने की बात सामने आने के बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले उपराजस्व निरीक्षक सीएस पुण्डीर ने एसडीएम को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह सरकारी जमीन लक्ष्मण झूला क्षेत्र की सराल ग्राम पंचायत, पट्टी उदयपुर तल्ला के गांव खैरखाल तोक में है। जिसका खसरा नम्बर 5889 है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी दस्तावेजों में यह जगह एक झाड़ी के रूप में दर्ज है। जिलाधिकारी ने वर्तमान राजस्व उप निरीक्षक वीएस गुसाई से दोबारा इस मामले में जांच करने को कहा जिसमें फिर इन आरोपों की पुष्टि हुई। इस प्रकार प्रेमचन्द से जुड़े मामले सामने आने लगे हैं।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

पिघलता हिमालय

शराब की दुकानों का विरोध

उत्तराखण्ड में जगह-जगह शराब की दुकान खोलने का विरोध हो रहा है। कौसानी में प्रस्तावित शराब की दुकान का विरोध कर रहे ग्रामीणों के साथ पद्मश्री राधा भट्ट भी शामिल हुईं। छानी-ल्वेशाल और कौसानी में शराब की दुकान का विरोध करते हुए ग्रामीणों सके साथ व्यापार मण्डल भी साथ है। बेरीनाग के उडियारी बैंड में प्रस्तावित दुकान का विरोध करने के लिये ग्रामीणों का प्रदर्शन हो रहा है। विधायक ने भी धरने में बैठने की चेतावनी दी। अल्मोड़ा में एसएसजे परिसर के पास दुकान खुलने की सुगबुगाहट से लोगों में रोष है। उनका कहना है कि छात्रों को किताबों से जोड़ने की बजाए शराब परोसी जा रही है। इन्दिरा कलोनी में शराब बार खोलने से गुस्साएं लोगों ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया। रानीखेत उपमण्डल के जालीखाल सोनी क्षेत्र में नई शराब की दुकान खुलने का पुरजोर विरोध होने लगा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला फूंक डाला। आबकारी विभाग द्वारा हर्षिल में शराब की दुकान खोलने के लिये निविदा जारी किये जाने पर स्थानीय लोगों और पांच मन्दिर समिति के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों ने तीर्थ पुरोहितों के साथ मिलकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार अन्य जगह भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

शराब की दुकान का विरोध करने के पीछे बहुत सीधी सी बात यह है कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और अपराधों से समाजिक जीवन जीने वाले डर रहे हैं। क्यों न डरें? बेरोजगारों का रेला, नशे का सामान, ऊपर से हिंसक व अपराधिक गतिविधयां। शराब के बढ़ते चलन से कई गड़बड़ियां हो रही हैं। एक ओर नशे से दूर रहने की बात कही जाती है दूसरी ओर राजस्व का लोभ शराब का कारोबार फैला रहा है।

यह भी तय है कि नशे की लत जिसे लग चुकी है उसे कोई नहीं रोक सकता। शराब की दुकान खुले या न खुले इससे शराबी को फर्क नहीं पड़ता। नजदीक खुलने से उसे सुलभ हो जाती है और न खुलने पर वह अतिरिक्त खर्च कर लाता या मंगवाता है। शराब की बेहिसाब दुकानों पर रोक होनी चाहिये। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि नशेपान की प्रवृत्ति ही न हो। ये सब हमारे अपने संयम रहने पर ही हो सकता है।

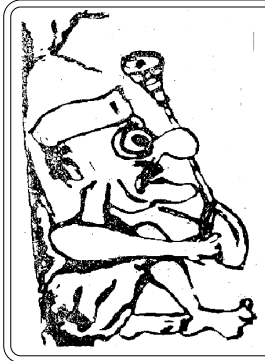

फसक

दाज्यू, छछुन्दरयोव हो रही ठैरी

वीडियो वायरल करने का भी अपना मजा होता है बल

दाज्यू, नैनीताल के मल्लीताल में शराब पीते सिपाही का वीडियो वायरल होते ही उसे लाइन हाजिर कर दिया गया। दाज्यू, जमाने में यही सब होने लगा है। एक-दूसरे की उघाड़ने के लिये तैयार बैठे हैं। बांकी आपको पता ही ठैरा कि चूं-चूं-छूं-छूं करने वाले सोशल मीडिया की बीमारी को ओढ़ने-बिछाने का काम कर रहे हैं।

दाज्यू, छछुन्दरयोव हो रही ठैरी। अपना माखनलाल बता रहा है कि उ.प्र. के हाथरस में पीसी बागला डिग्री कालेज के भूगोल विभाग के प्रभारी ने 50 से अधिक बालिकाओं का यौन शोषण कर दिया। पुलिस जाँच में 56 वीडियो सामने आये हैं जो प्रोफेसर ने खुद अपने मोबाइल से रिकार्ड की थीं। दाज्यू, लगता है घोर कलजुग में यही सब होना है। हमारे यहाँ पटरी पार वाले कालेज में भी बहुत गड़बड़ थी। भूगोल का पोपेसर आलमारी के पीछे घुसकर प्रेक्टिकल करवाता था बल। जब प्रयोगात्मक परीक्षा हो उस दिन बिल बनाने के लिये डण्डा-झण्डा लेकर खुले मैदान में फोटो खिंचवाता। दाज्यू, जालिम लोशन बाम साथ लेकर चलने वाले इस पोपेसर को हटाने के लिये बड़े बच्चों ने धरना-प्रदर्शन किया। इसी प्रकार का दूसरा पोपेसर देशी दवाखाने में इलाज करवाने की बात करता है बल। इसके आतंक से नगर और गाँव हिल चुके हैं। मतवाल सिंह कह रहा था- 'सरकारी और गैर सरकारी धनराशि को दीमक की तरह चाटने वाला मुंह में गोले का तेल लगाकर घूम रहा है।' दाज्यू, यह सब होगा जब मिलावट का दौर चल रहा हो। आगरा में किराये की दुकान में चार विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां बेचने वाला पकड़ा गया है बल। उसके पास से फर्जी प्रमाण पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं और लैपटॉप बरामद हुआ है।

दाज्यू, हम भगवान से हाथ जोड़ रहे हैं कि समाज की रक्षा करो। ऐसी छछुन्दरयोव में पता नहीं क्या जो न हो जाए। पूर्व विधायक प्रणव चैम्पियन भी जमानत पर जेल से बाहर है।

दाज्यू, छूं-छूं-चूं-चूं.....सब दौड़ रहे हैं। कालाढूंगी में भाजपाईयों ने यूट्यूबर बिरजू मयाल के खिलाफ पुलिस में तहरीर दे दी। दाज्यू, आप जानने ही वाले ठैरे कि बिरजू लट्ठमार व्यवहार का हुआ, जो जैसा लगा बक देने वाला ठैरा। चकमक बातें हर किसी को पसन्द नहीं आती हैं बल। उधर रुद्रपुर में विवादों में घिरा पार्षद से भाजपा ने किनारा कर लिया है। दो महिलाओं द्वारा छेड़छाड़ का आरोप के बाद पार्षद को पार्टी से हटाया गया है।

दाज्यू, बहुत गजबज होने लगी है। रामनगर रेंज के अन्तर्गत गांधीनगर खत्ता में कब्जा हटाने गई वन विभाग की टीम को लोड़या दिया। इस पथराव में सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गये और बुल्डोजर चालक को चोट आई है। जोधा सिंह, मेहताब सिंह सहित 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उधर देहरादून में महिला दरोगा से दुष्कर्म के मामले में सिपाही को जेल भेज दिया है बल। रुड़की में जमीन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने पर टोड़ा कल्याणपुर स्थित शंकरमठ आश्रम के संचालक स्वामी दिनेशानन्द को भी पुलिस ने पकड़ लिया है।

प्रेमचन्द जो जुवान....

प्रथम पृष्ठ का शेष

भट्ट, विस अध्यक्ष ऋतु खण्डूरी के रवैये की आलोचना की गई। सभा में पहाड़ बनाम मैदान के मुद्दे की राजनीति की निन्दा की। वक्ताओं ने कहा कि एक ओर भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करती है दूसरी ओर भू-कानून में मैदान के जनपदों को रियायत देने की बात करती है। जबकि मैदानी जिलों में जनसंख्या घनत्व तेजी से बढ़ रहा है। यदि भविष्य में परिसीमन होगा तो यह प्रदेश पर्वतीय क्षेत्रों के अपेक्षित विकास के लिये घातक होगा। इसके साथ ही राज्य गठन का मूल औचित्य ही समाप्त हो जायेगा।

उत्तराखण्ड स्वाभिमान मोर्चा के बॉबी पंवार का कहना है कि उत्तराखण्ड वासियों के स्वाभिमान की लड़ाई को जोरदार ढंग से लड़ा जाएगा। बेरोजगरी के मामले पर फोकस किया जाएगा। प्रेमचन्द को पद से हटाना लोकतन्त्र की जीत है। साथ ही विधायक बुटोला के समर्थन में उनके कांग्रेस विधायकों का चुप रहना भी सवाल है। यह लड़ाई अब आगे तक जारी रहेगी। इस प्रदेश को सही दिशा में ले जाना होगा।

MARTOLIA FURNITURE
Modular Kitchen, Sofa Set, Dinning Table, TV Cabinet, Dressing Table, Bed Room Furniture
Drawing Room Furniture & Interior, Restaurant Furniture & Turnkey Project.
Add : Near Devendrapuri, Badi Mukhani, Pilikothi Road, Haldwani Mob. : 8057167777, 7906752084, 8650427229

घर से बाहर अपनों का साथ
होटल लक्ष्य इन
मदकोट
सम्पर्क
नरेन्द्र सिंह रावत
7351285555

कपूर एण्ड संस
संजय कलोनी, मुखानी हल्द्वानी
कपूर इण्टरप्राईजेज
निकट मंगलम बैंकट हॉल, देवलचौड़
रामपुर रोड, कैंची धाम मार्ग हल्द्वानी
9997712279 9837824462

जंगपांगी जनरल स्टोर
मदकोट रोड,
दरांती मनुस्यारी
(सीमेन्ट, पेण्ट, हार्डवेयर सामग्री के लिये सुलभ स्थान)
मो.- 9760342346

होटल माँ नन्दादेवी एण्ड बारातघर
मो.न.
8958525979,
9411134775
नानासेम, मुनस्यारी
फोन सम्पर्क-
गणेश सिंह मर्तोलिया एण्ड सन्स 05961-222236
हार्डवेयर, बिल्डिंग मैटीरियल, जनरल आर्डर सप्लायर्स

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

हालातों पर

कुलपति बनने वालों की जवाबदेही भी तय हो

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

विश्वविद्यालय के कुलपति का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। एक लीडर और संस्था के प्रमुख होने के नाते, विश्वविद्यालय के कुलपति को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। अकादमिक योग्यताएं, प्रशासनिक अनुभव, अनुसंधान प्रमाण-पत्र और ट्रैक रिकार्ड एक कुलपति का होना चाहिए। कुलपति, विश्वविद्यालय के साथ-साथ छात्रों की बेहतरी के प्रति अपने आचरण में एक स्पष्टता बनाए रखता है। एक कुलपति ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को प्रेरित कर सके और विश्वविद्यालय प्रणाली में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों के प्रवेश की गारंटी दे सके। कुलपति एक विश्वविद्यालय के कार्यकारी और अकादमिक विंग के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है क्योंकि वह एक 'शिक्षक' और 'प्रशासक' दोनों का प्रमुख होता है। किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति पद के चयन के लिए यूजीसी के नियमानुसार एक सर्च कमेटी होती है। समिति का अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित एक कुशल योग्य व्यक्ति होता है, एक सदस्य यूजीसी के द्वारा नामित होता है, एक सदस्य सम्बन्धित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से नामित होता है, किन्ही राज्यों में इस सर्च कमेटी का सदस्य तत्कालीन सरकार का नामित सदस्य भी होता है। ऐसा भी देखा गया है कि किसी राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित एक सदस्य होता है। इस कुलपति सर्च कमेटी का मुख्य उद्देश होता है कि वह कुलपति पद के लिए आए हुए आवेदन पत्रों की जाँच करें और जाँच करके उनके अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार के अनुभव के आधार पर 3 या 5 सदस्यों का एक पैनल बनाता है।यह पैनल राज्यों के अनुसार या तो मुख्यमंत्री के पास या राज्य के राज्यपाल के पास दे दिए जाते हैं। 3 या 5 सदस्यों के पैनल से माननीय मुख्यमंत्री या और माननीय राज्यपाल दोनों के निरीक्षण के बाद सम्बन्धित विश्वविद्यालय के लिए कुलपति का नाम चयनित किया जाता है। यह अत्यन्त दु:ख की बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय के कुलपति चयनित होने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा यह मालूम होता है कि चयनित कुलपति की नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई। कुलपति के द्वारा आवेदन पत्र में शैक्षणिक या अकादमिक या प्रशासनिक दस्तावेजों से सम्बन्धित सूचनाएं गलत पेश की गय्र थी। चयनित कुलपति यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार योग्यता नहीं रखते थे।

जब ऐसे समाचार मिलते हैं माननीय न्यायालय असंवैधानिक रूप से चुने गए कुलपतियों को उनके उनके पद से विमुक्त कर दिया जाता है तब बहुत दु:ख होता है। मन में एक प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के दोष के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। अक्सर साधारण तौर पर माननीय राज्यपाल या माननीय मुख्यमंत्री की ओर इशारा किया जाता है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जाना चाहिए कि आधिकारिक रूप से नियुक्त एक सर्च कमेटी के सदस्यों की क्या भूमिका है? साधारण तौर पर इस पूरी चयन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उस कार्यालय की जिम्मेदारी होती है जिसमें कुलपति पद के लिए आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। उस कार्यालय की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए की आवेदनकर्ता से मांगे गए सभी दस्तावेज प्रेषित किए हैं या नहीं और उन सभी दस्तावेज के बारे में गम्भीर रूप से अध्ययन करना चाहिए कि दस्तावेज में कोई कमी तो नहीं है और यदि दस्तावेज में कोई कमी है तो उसको चयन समिति के सदस्यों को बताना चाहिए। सर्च कमेटी के सदस्य के नाते कुलपति का नाम प्रस्तावित तो करते हैं लेकिन वास्तव में वह कुलपति के लिए प्राप्त आवेदकों को आवेदन पत्रों को बिल्कुल जाँच नहीं करते और उनके पास प्रस्तावित नामों की सूची पहले से ही या तो राज्य सरकार के द्वारा या अन्य माननीय व्यक्तियों के द्वारा दे दी जाती है। वह तो केवल हस्ताक्षर मात्र ही करते हैं। यदि यह सही है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है इस प्रकार के प्रकरण की गम्भीरता से जाँच होनी चाहिए।

किसी भी विश्वविद्यालय के लिए इस प्रक्रिया से कुलपति चुनना बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामला है और पूरे नियमों का पालन करने के बाद भी एक सबसे आदर्श कुलपति का चुनाव हो जाए यह भी कहना उचित नहीं होगा लेकिन यदि कुलपति पद के चुनाव के लिए कुछ नियमावली है तो उस नियमावली का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। कुलपति चयन प्रक्रिया में एक और भी गम्भीर प्रश्न है जब एक कुलपति की नियुक्ति के बारे में प्रश्न चिन्ह उठते हैं और कोई प्रभावित व्यक्ति न्यायालय में अपील करता है तब न्यायालय की अपनी व्यवस्था के अनुसार प्रक्रिया होती है। न्यायालय की प्रक्रिया के पूर्ण होने में इतना समय लग जाता है की तत्कालीन कुलपति का कार्यकाल स्वत: ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार न्यायालय में अपील करने से ही कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता और नियुक्ति में हुई धांधली को या कोई असंवैधानिक प्रक्रिया का समाधान नहीं हो पाता है। आने वाले समय मे फिर आम व्यक्ति गलत चयन प्रक्रिया की अपील न्यायालय ले नहीं करते और गलत चयनित व्यक्ति अकादमिक का सत्यानाश कर देते हैं। कुलपति के चयन में या किसी भी संस्थान के मुखिया के चयन में यदि कोई न्यायिक प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है तो उस पर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय का निर्णय आ जाना चाहिए क्योंकि यदि अकुशल, अयोग्य व्यक्ति किसी संस्थान के उच्च पद पर लम्बे समय तक रह गया तब उस संस्थान के भविष्य एक चिन्ता का विषय रहता है। अत: माननीय न्यायालय को शीघ्र से शीघ्र अपना निर्णय लेना चाहिए। विश्व विद्यालयों को तभी श्रेष्ठ कुलपति मिल सकते हैं जब चयन को लेकर गठित पैनल में अनुभवी शिक्षाविद शामिल हों और जो बिना किसी दबाव के पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर कुलपति का चयन करें।

यूजीसी द्वारा 18 जुलाय्र, 2018 को भारत के राजप> में जारी अधिसूचना के अनुसार व्यवसायिक आचार संहिता के अन्तर्गत शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। जिसमें एक शिक्षक से उनकी 'कथनी और करनी' के बीच भेद न करने की अपेक्षा की गई है। चूंकि इन्हीं शिक्षकों में से ही कुलपतियों का चयन होता है इसलिए यह बात कुलपतियों पर भी लागू होती है। इसी अधिसूचना में कुलपतियों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनके अनुसार एक कुलपति को पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करने एवं विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने के लिए कहा गया है। कुलपति के चयन के लिए निकाले गये विज्ञापन में इन सब बातों का उल्लेख तो रहता है, लेकिन इन कुलपतियों के कुलपति बनने के पहले के एक-दो माह की कॉल डिटेल एवं कॉल रिकार्डिंग निकलवा ली जाए, तो अधिकतर कुलपतियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकते हैं क्योंकि ये साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति पर अमल करते हुए कुलपति बनने एवं बने रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं कुलपति चयन करने वाली समिति के सदस्यों की कॉल डिटेल एवं कॉल रिकाह्डग सामने आ जाये तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जायेगी। यदि कुलपति बेहतर एवं निष्पक्ष रूप से काम कर रहें हैं तो सार्वजनिक रूप से उनका एवं उनको नियुक्त करने वालों का सम्मान भी होना चाहिए। वर्तमान में जो कुलपति निष्पक्ष रूप से एवं अच्छा कार्य कर रहें हैं वे भी इस बात से सहमत होंगे कि कुलपति नियुक्त करने की प्रक्रिया पर पुर्नविचार की आवष्यकता है। चयन समिति को यह अधिकार भी दिया जाना चाहिए, जिससे वे कुलपति के लिये आवेदन न करने वालों के नाम पर भी विचार कर सकें। यूजीसी द्वारा ईमानदारी, नैतिकता एवं निष्पक्षता को आधार मानकर शिक्षकों की एक सूची तैयार करनी चाहिए, जिसमें अनुशंसा करने वालों के नाम भी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हों। शिक्षक सिर्फ वे बनें, जिनमें देने का भाव हो तथा जिनकी 'कथनी और करनी' में अन्तर न हो। समवर्ती सूची में आने के कारण शिक्षा पर संघ एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। देश में कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर न्यायालयों में वर्षों से विचाराधीन प्रकरण इस बात का प्रमाण हैं कि अभी तक पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देश भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद राज्यों में किस तरह से लागू होंगे। यदि राज्यों को इन्हें लागू न करने का अधिकार है तो इसका भी उल्लेख होना चाहिए। यदि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाये तो कुलपति की नियुक्तियों को लेकर विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण बहुत जल्दी हो सकता है। चूंकि कुलपति की चयन समिति में एक सदस्य यूजीसी का रहता है इसलिए इस तरह के प्रकरणों में इस सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक चलने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में आने वाले निर्णयों के आधार पर जबावदेह अधिकारियों की पहचान होनी चाहिए। जब तक अनावष्यक रूप से न्यायालयीन प्रकरणों को जन्म देने एवं उन्हें लम्बित करने वाले अधिकारियों की जबावदेही तय नहीं होगी तब तक न्यायालयीन प्रकरणों में कमी नहीं आयेगी। हमें आकलन के पैमानों पर पुर्नविचार करना होगा क्योंकि जो कभी गाँव में नहीं रहे वे ग्रामीण विकास पर निबन्ध लिखकर बड़ी-बड़ी प्रतियोगी परीक्षायें पास कर रहे हैं। दो साल पहले चेन्नई में एक आई.पी.एस. अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गये थे। हमारे आकलन की इससे बड़ी विसंगति और क्या होगी कि 2014 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इन्होंने ईमानदारी एवं नैतिकता जाँचने वाले प्रश्नपत्र में अन्य प्रश्नपत्रों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किये थे। ईमानदारी, नैतिकता एवं सम्वेदन शीलता चयन की पहली शर्त होनी चाहिए। कुलपति का चयन करते समय अकादमिक उपलब्धियों के साथ-साथ सम्बन्धित संस्था से ईमानदारी, नैतिकता एवं सम्वेदनशीलता के सम्बन्ध में गोपनीय जानकारी भी हासिल की जानी चाहिए।

ज्योतिष की बातें- 222

3 अप्रैल 2025 को मंगल नीचराशि कर्क में प्रवेश करेगा। वहाँ पर कोई शुभाशुभ दृष्टि भी नहीं होगी। इस कारण मंगल अत्यन्त निर्बल रहेगा। मंगल स्वास्थ्य, धौर्य, कर्मठता, साहस, पुरुषार्थ, कर्तव्य परायणता, नेतृत्व क्षमता, दृढ़ निश्चय, युद्ध एवं खेलकूद, शत्रु पर विजय, भूमि-भवन-वाहन का लाभ, यश एवं कीर्ति, मशीनरी, इंजीनियरिंग एवं विद्युत का कारक होता है। फलदीपिका के अनुसार मंगल त्रिषडाय (अर्थात् तीसरे, छठवें और ग्यारहवें) भावों में शुभफल प्रदान करता है। साथ ही कर्क एवं सिंह राशियों के लिए मंगल योगकारक होता है। अत: अगले 63 दिन मंगल अपने कारक विषयों में वृषभ, कर्क, सिंह, कुम्भ एवं कन्या राशि के जातकों को सामान्य शुभफल प्रदान करेगा।

6 अप्रैल 2025 को बुधा मीन राशि में पूर्व दिशा में उदय हो जाएगा अत: बुध से प्राप्त होने वाले फल अब स्पष्ट रूप से प्राप्त होंगे।

रामनवमी- चौत्र शुक्ल नवमी मध्याह्न व्यापिनी तिथि में श्री रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। तदनुसार रविवार 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा।

यहाँ पर प्रत्येक ग्रह का गोचरफल अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति विशेष के लिये सूक्ष्म विश्लेषण उसकी जन्मकुण्डली, महादशा आदि पर निर्भर करता है।

शुभं भवतु !!

-ओंकार नाथ कोष्टा
ज्योतिर्विद् एवं आयुर्विद्

सम्यक् विचार- 113

कन्या की खोज

आजकल लड़के के विवाह में बहुत दिक्कत आ रही है। यदि लड़के की उम्र 25 वर्ष बताई जाती है तो इससे अधिक उम्र की लड़कियाँ तो तैयार ही नहीं होगी और इससे कम उम्र की बीस-बाइस वर्ष की लड़कियाँ विवाह के लिए उपलब्ध ही नहीं होती है क्योंकि इस उम्र में वे अपना कैरियर बनाने में व्यस्त होती हैं। यदि लड़के की आय बताई जाए '10लाख का पैकेज' तो इससे अधिक कमाने वाली लड़कियां सामने आएंगी ही नहीं तो अधिकांश लड़कियाँ वहीं पर छंट जायेंगी। यदि लड़के को मंगली बताया जाता है तो नान मंगली लड़कियाँ सामने आती ही नहीं है और यदि लड़के को नॉन मंगली बताया जाए तो मंगली लड़कियाँ सामने नहीं आयेंगी। इस प्रकार आधी लड़कियाँ वहाँ भी छंट जाती हैं। यदि लड़का कहता है की शादी के बाद लड़की को उसके साथ ही रहना पड़ेगा अर्थात् उसके ही शहर में सर्विस करनी होगी तो यह बहुत कठिन हो जाता है।

यदि लड़का सच-सच यह बोल देता है कि वह नौकरी करने वाली लड़की नहीं चाहता तो ऐसी लड़की मिलना अब दुर्लभ हो गया है क्योंकि सभी लड़कियाँ उच्चशिक्षित होकर अब नौकरी कर रही हैं । यदि किसी तरह सारी बातें मिल भी जाती हैं तो अन्त में दोनों की जन्मकुण्डली पण्डित जी से मिलवाई जाती है। लेकिन आजकल अधिकांश ज्योतिषियों का उत्तर यही मिलता है कि कुण्डली नहीं मिल रही है, यह विवाह नहीं हो सकता। इसके बाद फिर से नई खोज शुरू हो जाती है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि विवाह की उम्र निकल न जाए।

इस प्रकार की समस्या सम्पूर्ण समाज में व्यापक रूप से फैल चुकी है। मेरे विचार से इस समस्या का मुख्य कारण है 'नारी सशक्तिकरण की योजना'। ऐसी स्थिति में वे लड़के भाग्यशाली है जिन्होंने प्रेम प्रकरण के माध्यम से स्वयं ही अपना घर बसा लिया है ।

-ओंकार नाथ कोष्टा

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

महेशपुरा क्षेत्र में ओवरब्रिज की मांग

बाजपुर। एनएच-74 पर ग्राम महेशपुरा क्षेत्र में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिये गांव के बीच ओवरब्रिज बनवाने की मांग उठी है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए ओवरब्रिज बनवाने की मांग की है।

रोडवेज की भूमि पर कब्जा हटाया

रुद्रपुर। उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने रोडवेज की भूमि पर लम्बे समय से कब्जा कर बैठे लोगों को हटाया है। तीस साल से कब्जा जमाए लोगों को हटाने के लिये जेसीबी चलाई गई। विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई करवाई।

मझेड़ा के ग्रामीणों का प्रदर्शन

लोहाघाट। मझेड़ा के ग्रामीणों ने गांव तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए सीएम को पत्र भेजा है। जिसमें कहा है कि दो साल पूर्व मानेश्वर-मझेड़ा के तहत खेतीगाड़ तक सड़क निर्माण की घोषणा की थी और वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई लेकिन कार्य आज तक अधर में लटका है। ज्ञापन देने वालों में आरसी पाण्डे, भुवन चन्द्र, गोपाल दा आदि थे।

सिर्खा में मकान में आग लगी, नुकसान

धारचूला। तहसील मुख्यालय से 55 किमी दूर सिर्खा गांव के आवासीय भवन में लगी भीषण आग के साथ 5 गौशालाएं जल गईं। इसमें काफी नुकसान हुआ। किशोर सिर्खाल ने बताया है कि अग्निकाण्ड से पूरा गांव दहशत में है।

थल-डीडीहाट सड़क दुरुस्त होगी

थल। डीडीहाट तहसील मुख्यालय को थल से जोड़ने वाले अल्मोड़ा-बेरीनाग-अस्कोट राजमार्ग के अधीन आने ली थल-डीडीहाट-ओगला सड़क को इस बार दुरुस्त कर दिया जायेगा। इसमें सात किमी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। इसके नवीनीकरण के लिये शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। इसी प्रकार मुवानी से डीडीहाट आवागमन केरने वालों को भी दुरुस्त सड़क देखने को मिलेगी।

उडियारी में शराब दुकान का विरोध

बेरीनाग। शहर से सात किमी दूर थल मार्ग पर उडियारी बैंड में शराब की दुकान खोले जाने की सुगबुगाहट पर ग्रामीणों ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया। भारी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि इलाके में शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिये। आन्दोलनकारियों का कहना है कि वह पानी की मांग कर रहे हैं परन्तु उनकी सुनवाई के बजाय देशी शराब की दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है। शराब की दुकान इलाके में बर्दाश्त नहीं होगी।

कमिश्नर की मोदी से की शिकायत, लगाए संगीन आरोप

16साल की सेवा में 13साल नैनीताल में बिताने, प्रापर्टी डीलर व बिल्डरों के हाथों खेलने का आरोप

हल्द्वानी। भीमताल के एक व्यक्ति ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस व्यक्ति ने रावत की शिकायत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री, रक्षा मंत्री समेत देशभर के अनप्रतिनिधियों से की है। इसमें आयुक्त के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए हैं। यही नहीं दीपक रावत पर केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का नजदीकी परिचित व रिश्तेदार होने की वजह से असंवैधानिक कार्य करने का भी आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि 16 साल की सेवा के दौरान दीपक रावत तेरह साल केवल नैनीताल में ही रहे हैं।

शिकायतकर्ता विकास भारती का कहना है कि पर्यटक नगरी भीमताल का अस्तित्व दिन प्रतिदिन समाप्त हो रहा है। भीमताल को कंक्रीट का के जंगल में बदल दिया गया है। यह बिल्डर व प्रापर्टी डीलरों द्वारा कई तरह के अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इनको हटाने के बजाए आयुक्त कम्पार्टमेंटिंग की आड़ में नियमित कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि आयुक्त रावत के मामले में स्थानान्तरण नियकतों तक का पालन नहीं किया जा रहा है। तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद इनको नैनीताल से नहीं हटाया गया। आरोप में यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी रहते हुए इन्होंने खनन के 50 करोड़ रुपये अर्थदण्ड की धनराशि को माफ करने का हैरतअंगेज कार्य भी किया है। यह मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है।

भारती का कहना है कि 2009-10 में दीपक रावत, आईएएस की तैनाती एसडीएम हल्द्वानी के पद हुई थी। इसके बाद इनको सीडीओ नैनीताल का चार्ज दिया गया था। 2011 में बागेश्वर का जिला कलेक्टर बनाया गया था लेकिन नैनीताल जनपद से मोह होने के कारण इन्होंने स्थानान्तरण एक साल से कम अवधि में ही सन् 2012 में एमडी कुमाऊं मण्डल विकास निगम नैनीताल के पद पर करवा लिया था। जबकि शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत पांच साल से पहले कोई भी स्थानान्तरित अधिकारी

उसी जनपद में स्थानान्तरित नहीं हो सकता है। 2014 में दीपक रावत को जनपद नैनीताल में जिला अधिकारी बनाया गया। 2017 तक जिला अधिकारी नैनीताल के पद पर कार्यरत रहे थे। 2017 में दीपक रावत को जनपद हरिद्वार में जिलाधिकारी बनाया गया। इसके बाद 2021 कुमाऊं आयुक्त बनाकर नैनीताल भेज दिया गया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष पद पर भी दीपक रावत तैनात हैं। इस प्रकार देखा जाए तो उनकी लगभग 16 साल की सेवाओं में इनके द्वारा 13 साल नैनीताल जिले में बिताए हैं। जबकि उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी आईएएस, पीसीएस, आईपीएस अधिकारी 16 साल की अवधि में एक ही जनपद पर 13 साल की अवधि पूरी नहीं कर सका है।

भारती का कहना है कि रावत ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राजेश नेगी मनोज नेगी द्वारा भीमताल क्षेत्र में पुलिस थाना भीमताल के समीप 2016 में सील हो चुकी बिल्डिंग में शराब बार को बन्द करने के मामले को दबाने की कार्रवाई की जा रही है। यहीं नहीं उत्तराखण्ड राज्य में लोकसभा चुनाव की चुनाव आचार संहिता के दौरान ही भीमताल महायोजना में परिवर्तन करते हुए नौकुचियाताल के पास 9000 मीटर भूमि पर व्यावसायिक निर्माण होटल निर्माण इत्यादि करने की स्वीकृति को भी दी गई है। इसकी पुष्टि पत्रावलियों की जांच करके भी हो सकती है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिये उत्तराखण्ड राज्य की भूमि कानून का उल्लंघन भीमताल महायोजन को ग्रीन बेल्ट की भूमि को ही बदल दिया गया है। भारती ने कई आरोप लगाए हैं।

नैनीताल में पर्यटकों को देना होगा ग्रीन टैक्स

नैनीताल। सरोवरी नगरी आने वाले पर्यटकों को अब ग्रीन टैक्स देना होगा। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। यह टैक्स मुख्य रूप से वाहनों पर लागू होगा, जिससे नगर में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों को ग्रीन टैक्स के रूप में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

टनकपुर अस्पताल में रैन बसेरा तैयार

टनकपुर। उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में उपचार के लिये दूरदराज से आने वाले मरीजों के तीमारदारों के ठहरने के लिए रैन बसेरे का निर्माण हो चुका है। 17.08 लाख की लागत से बने रैन बसेरे में 20 लोग रह सकते हैं। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग ने भवन को अस्पताल प्रशासन को हस्तान्तरित करने की तैयारी शुरू कर दी है। रैन बसेरे का संचालन शुरू होने के बाद मरीजों के तीमारदारों को ठौर मिलनी शुरू हो जायेगी। अब तक मरीजों को भर्ती कराने के बाद रात में रुकने के लिये होटलों या ध र्मशाला के भरोसे रहना पड़ता था। उपजिला चिकित्सालय टनकपुर एवं बनबसा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी मरीज इलाज के लिये आते हैं। गम्भीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के बाद उनके तीमारदारों को ठहरने के लिये यत्र-तत्र चक्कर काटने पड़ते हैं। भीड़ के कारण या मेला अवधि में तीमारदारों को होटल में जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में यह रैन बसेरा सहारा बनेगा।

रानीखेत में उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा

रानीखेत। उननिदेशक रक्षा सम्पदा मध्य कमान लखनऊ के रानीखेत छावनी कर्यालय पहुंचने पर छावनी के नामित सदस्य मोहन नेगी ने उनसे मुलाकात करते हुए छावनी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा है कि रानीखेत छावनी क्षेत्र में वर्षों से निवास कर रहे लोगों को ब्रिटिश शासकों ने नॉमिनल लीज पर 30 वर्षों के लिये खेती फल व सब्जी के उत्पादन हेतु भूमि प्रदान की थी। जिससे उन्हें ताजी सब्जियां, फल यहीं उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन 100 वर्षों बाद आजाद भारत में अब न तो लीज का नवीनीकरण किया जा रहा है न लीज धारक भूमि पर गौ पालन व सब्जी उत्पादन कर पा रहे हैं। लीज पॉलिसी न होने से मात्र एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किय जा रहा है व लीज रेट भी बहुत अधिक है। जनहित में इन व्यवहारिक बातों का हल किया जाना चाहिये।

हल्द्वानी की सड़कों पर सिटी बसें होंगी

हल्द्वानी। शहर के 6 प्रमुख रूटों पर 168 किमी के दायरे में 21 जून से सिटी बसें दिखाई देंगी। शुरुआती चरण में 20 से 25 बसें चलाई जाने की योजना है। साथ ही कैंची धाम, भीमताल और नैनीताल सहित अन्य रूटों पर भी बसें चलाई जाएंगी। ये बसें 20 से 24 सीटर होंगी, जिससे शहर की सड़कों के अनुसार आसानी से इनका संचालन होगा। काठगोदाम सर्किट हाउस में आरटीए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में सिटी बसों के साथ ही नई बसों के परमिट दिए जाने, रूटों पर बसें चलाने के लिये सर्वे किये जाने आदि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आवेदनकर्ताओं को बसें खरीदने और प्रक्रिया पूरी करने के लिये लगभग तीन माह का समय दिया जाएगा। 21 जून से बसें संचालन शुरू करने को कहा गया है। बैठक में आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि सिटी बसों के संचालन से बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सकेगा।

आपके पत्र

ज्योलीकोट की समस्याओं का निदान किया जाए

वर्ष 2022 में अन्य राज्यों के साथ उत्तराखण्ड विधानसभा का भी नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार का गठन हुआ प्रदेश की जनता को पूर्ण उम्मीद थी कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में गठित उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश का चहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास करेगी। धामी जी में विकास पुरुष पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी जी की छवि देखने को मिली थी, इसी उम्मीद के साथ ज्योलीकोट ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए इसके निदान की प्रार्थना की गई थी। उसके पश्चात कई बार स्मृति पत्र भी प्रेषित किया जाता रहा तथा मा. सांसद नैनीताल क्षेत्र अजय भट्ट जी को भी उक्त समस्याओं से अवगत कराते हुए निवेदन पत्र भेजा गया लेकिन ज्योलीकोट की समस्याओं का निदान नकारात्मक ही रहा। बाद में अक्टूबर 2023 में ज्योलीकोट में विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा शिविर भी लगाया गया परन्तु फिर भी परिणाम नकारात्मक ही साबित हुआ। इस प्रकार उक्त मामले को तीन वर्ष व्यतीत होने पर भी कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला।

ऐसा मालूम होता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग (वरिष्ठ नागरिकों) के प्रेषित निवेदन पत्रों को उनके प्रति सम्मानित भाव न लेकर हल्केपन में लेते हुए ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाता है। कुमाउंनी में कहावती है कि तेरि पैलाग मेरी भैंस क सींग में, यही कहावत सिद्ध हुई है।

माननीय मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी जैसे उदार एवं प्रगतिशील मुख्यमंत्री से यह आशा नहीं थी कि उनकी सरकार में ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार न करके निराशाजनक परिणाम मिलेंगे। यद्यपि यह उम्मीद की गयी थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं ज्योलीकोट की ग्रामीण जनता से मुलाकात करेंगे तथा यहाँ की समस्याओं पर सकारात्मकता से विचार करके क्षेत्र का विकास करायेंगे। स्वयं मुख्यमंत्री भ्रमण करके या तो सरकार का कोई प्रतिनिधि या कोई जिम्मेदार अधिकारी क्षेत्र के भ्रमण पर आकर जनता का मनोबल ऊँचा करने हेतु सम्पर्क करेंगे। इसी क्रम में आग्रह के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

-नन्दा बल्लभ पाण्डे
वरिष्ठ नागरिक एवं संरक्षक
गवर्न0पेंशनर्स वेलफेयर संगठन
ज्योलीकोट (नैनीताल)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तराखण्ड शासन

देवभूमि रजत उत्सव

सेवा, सुशासन एवं विकास के 3 साल

“ 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। ”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

“ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक कहा है। हम प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप राज्य को हर क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिये विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। ”

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

संकल्प नये उत्तराखण्ड का

विकसित भारत - सशक्त उत्तराखण्ड

पर्यटन

उत्तराखण्ड के जखोल, सूपी, हर्षिल और गुंजी गांवों को भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया गया।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत सीमांत के 51 गांवों का चयन कर किया जा रहा सुनियोजित विकास।

कुशल प्रबंधन से चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड संख्या में आए श्रद्धालु।

राज्य में पहली बार शीतकालीन यात्रा का हुआ शुभारंभ।

मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत 48 मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक स्थलों को सर्किट के रूप में जोड़ने का कार्य गतिमान।

महासू मन्दिर, हनोल के मास्टर प्लान को दी गई मंजूरी।

कनेक्टिविटी

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा केवल 2.5 घंटे में पूरी होगी।

गौरीकुण्ड से केदारनाथ एवं गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक रोपवे निर्माण कार्य को मिली केंद्र सरकार से स्वीकृति। पूर्णागिरी मंदिर रोपवे, काठगोदाम से हनुमानगढ़ी के बीच रोपवे के निर्माण कार्य हेतु प्रक्रिया शुरु।

उड़ान योजना के तहत शुरु की गई देहरादून पिथौरागढ़ उड़ान सेवा ने दोनों शहरों के बीच यात्रा की अवधि को सड़क मार्ग से 12-15 घंटे से घटाकर केवल 60 मिनट कर दिया है।

ऋषिकेश - कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना गांवों को शहरो से जोड़ने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।

₹10,000 करोड़ की भारतमाला परियोजना को सीमा क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए स्वीकृत किया गया।

2030 तक उत्तराखण्ड के सभी गांव सड़क से जुड़ेंगे।

युवा-शिक्षा, रोजगार, सौर स्वरोजगार

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनाः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, सोलर प्लांट स्थापित करने पर 50% तक सब्सिडी

पिछले 3 वर्षों में लगभग 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की हुई शुरुआत।

राज्य में पिछले एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4 प्रतिशत की कमी।

उद्योग एवं निवेश

एमएसएमई नीतिः नए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन

ऊधमसिंह नगर के खुरपिया फॉर्म में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्वीकृत।

इन्वेस्टर्स समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू, 30 निवेश अनुकूल नई नीतियां, लगभग 85 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग पर कार्य गतिमान।

महिला सशक्तिकरण

हाउस ऑफ हिमालयाज, उत्तराखण्ड महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध

राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण

लखपति दीदी योजनाः महिला स्वयं सहायता समूहों को `5लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण

को-ऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत राज्य के करीब पौने दो लाख गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त रिफिल।

बड़े निर्णय-बड़े प्रभाव

समान नागरिक संहिता, सशक्त भू-कानून, राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण, सख्त धर्मान्तरण विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, दंगों में सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून

बड़े आयोजन

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2023: उत्तराखण्ड को लक्ष्य से अधिक 3.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

इन्वेस्टर्स समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू, 30 निवेश अनुकूल नई नीतियां, लगभग 85 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग पर कार्य गतिमान।

जी-20 सम्मेलन की बैठकें: जी-20 सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठकों का उत्तराखण्ड में सफल आयोजन।

38वें राष्ट्रीय खेल: देवभूमि को रजत जंयती वर्ष के अवसर पर 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर एवं सफल आयोजन।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन: विभिन्न देशों में रहते हुए व्यापार व अन्य क्षेत्रों में नाम कमाने वाले प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपने साथ जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो: दिसंबर 2024, देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रैंकिंग में उत्तराखण्ड देश में प्रथम स्थान पर

- समान नागरिक संहिता: सबका साथ सबका विकास
- सख्त धर्मान्तरण विरोधी कानून: जबरन धर्मान्तरण पर रोक
- रेल, रोड, रोपवे और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in | uttarakhandDIPR | DIPR_UK | uttarakhand DIPR

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

क्वारब मार्ग पर 11 अप्रैल तक रात्रि वाहनों पर रोक

अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे में क्वारब पुल के पास बने डेंजर जोन में रात्रि में आवाजाही को फिर से रोका गया है। क्वारब पुल के पास बन रहे खतरे को देखते हुए आगामी 11 अप्रैल तक रात में 11 से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बन्द रहेगी। डलएम आलोक कुमार पाण्डे की ओर से आदेश जारी किया है। असल में अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्टीय राजमार्ग के क्वारब के पास दरक रही पहाड़ी खतरा बनी हुई है। बीते 6 माह से अधिक समय से यहां रात में वाहनों का संचालन पूरी तरह ठप है लेकिन इसके बाद भी अब तक दरक रही पहाड़ी की रोकथाम के लिये कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। जिससे यहां से गुजरने वाले यात्रियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पहाड़ी से खतरे की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन क्वारब मार्ग के पास रात्रि में आवाजाही रोक पाने के अलावा कर भी क्या सकता है? अब इसको 11 अप्रैल तक बन्द किया है।

चारधाम, हेमकुंड साहिब यात्रा का पंजीकरण

30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा, 60 फीसदी ऑनलाइन और 40 फीसदी ऑफलाइन होंगे पंजीकरण

देहरादून। चारधाम और हेमकुण्ड साहिब यात्रा 2025 के लिये ऑनलाइन पंजीकरण जारी हैं। इस बार पंजीकरण के साथ्ज्ञ आधार नम्बर की जानकारी देना जरूरी होगा।

बद्री-केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री तथा हेमकुण्ड साहिब जाने के इच्छुक तीर्थ यात्री उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले दिन 1.50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा चुके थे। इस वर्ष की चारधाम यात्रा का अक्षय तृतीया के पर्व पर 30 अप्रैल से उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री मन्दिर के कपाट खुलने के साथ शुभारम्भ हो जायेगा। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट दो मई को और चमोली जिले में स्थित बदरीनाथ धाम के कपाट चार मई को खुलेंगे। इसके अलावा हेमकुण्ड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू होगी। अधिकारियो ने इस सम्बन्ध में बताया कि इस बार राज्य सरकार ने 60 फीसदी ऑनलाइन पंजीकरण के साथ-साथ 40 फीसदी ऑफलाइन पंजीकरण का निर्णय लिया है जिससे इन्टरनेट का उपयोग नहीं कर पाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। ऑफलाइन पंजीकरण हरिद्वार व ऋषिकेश के साथ यात्रा मार्गों पर केन्द्रों पर कराए जा सकेंगे।

पद्मश्री डॉ.तितियाल का हल्द्वानी में भव्य स्वागत

हल्द्वानी। एम्स के नेत्र विशेषज्ञ रह चुके पद्मश्री डॉ. जीवन सिंह तितियाल का हल्द्वानी पहुंचने पर दिल्ल दर्मा सेवा समिति ने भव्य स्वागत किया गया। फतेहपुर स्थित रं मिलन भवन खेमपुर में अपनी पत्नी बसन्ती तितियाल के साथ पधारे डॉ. तितियाल के स्वागत के लिये बड़ी संख्या में जन उपस्थित थे। पारम्परिक वेशभूषा में स्वागत गीत सहित आयोजन हुआ। इस अवसर पर सुन्दर सिंह बोनाल, डॉ. गोविन्द सिंह तितियाल, अपर आयुक्त जीवन सिंह नगन्याल, दिल्ल दर्मा सेवा समिति के अध्यक्ष करन सिंह ग्वाल, राम सिंह सोनाल, दीवान सिंह सोनाल, मोहन सिंह बंग्याल, रं कल्याण संस्था हल्द्वानी के अध्यक्ष चन्द्र सिंह सीपाल मौजूद थे।

'सिद्धार्थी' नाम नवसम्वत्सर, विक्रमी 2082 की हार्दिक शुभकानाओं के साथ-

ललित सिंह मर्तोलिया

'नवादा हाइट्स' बद्रीपुर जोगीवाला देहरादून

न तेरा न मेरा Thats
APNA GHAR चौकोड़ी
HOTEL RESTRO BANQUET
मो.- 9458920379, 6396098804
YOGA MEDITATION | LIVE MUSIC | HOMELY FOOD | BIRTHDAY WEDDING
Near by- (माँ कोटगाड़ी, नौलिंग देव, पातालभुवनेश्वर)
पितृछाया- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. जोगासिंह मर्तोलिया

Hotel
Bala Paradise
Tiksain, Munsiari
Ph. 05961222237, 9412951678

Hayat Paradise
Bus Station
Munsiari
Ph. 09411556700, 9997733070

धमोत होम स्टे
धरमघर/चकोड़ी
(एडवेंचर जोन, ट्रेकिंग, माउंटेन वाइकिंग, स्थानीय व्यंजन)
www.mountainheights.in
मो. 9760007148

Enjoy Beauty of Himalaya at
MARTOLIA LODGE
Family Guest House-
Sarmoly, Munsiyari
A Home Away From Home & Home Stay
Phone: (05961) 222287

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीमती गीता उप्रेती द्वारा पिघलता हिमालय, जे०के०पुरम्, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं शक्ति प्रेस, जे०के०पुरम्, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी(नैनीताल) से मुद्रित।

सम्पादकः श्रीमती गीता उप्रेती फोन/मोबाइल 9458961490, 9411770280, 9411301014,
editorpighaltahimalay@gmail.com
Website- www.pighaltahimalay.com

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)